भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 157

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात की बढ़ती संभार तंत्र लागत

***157. श्री चंदेश्वर प्रसाद:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या यह सच है कि भारतीय वस्तुएं विश्व बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हैं क्योंकि देश में निर्यात की संभार तंत्र लागत बहुत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की इस क्षेत्र में बढ़ती लागत, जिससे निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है, जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक पृथक संभार तंत्र विभाग बनाने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 157 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप भारत को प्रमुख भागीदार बनाने के लिए वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने, भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने तथा विभिन्न देशों और समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करने, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ निर्यात कार्यनिष्पादन की नियमित निगरानी करने, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्ड/प्राधिकरणों तथा उद्योग संघों के साथ विचार विमर्श करने के उपाय शामिल हैं तथा समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी) को नई विदेश व्यापार नीति की शुरुआत की गई थी। यह नीति भारत को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने तथा इसे विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार बनाने की रूपरेखा निर्धारित करती है।

वर्तमान में, भारत का निर्यात नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत का समग्र निर्यात 776 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है, जिसमें दो वर्ष की अवधि अर्थात् 2020-21 से 2022-23 के दौरान लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार के 7 जुलाई, 2017 के आदेश (कार्य आबंटन नियमावली) के जरिए लॉजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया था जो वर्तमान में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। इस प्रभाग को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का अधिदेश प्राप्त है।

सरकार ने लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का व्यापक विकास करने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरूआत की तथा 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति आरंभ की।

लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। पीएम गतिशक्ति एनएमपी आर्थिक नोड्स तक मल्टीमॉडल अवसंरचना कनेक्टिविटी की आयोजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है

जिससे लॉजिस्टिक्स में कुशलता आती है। एनएमपी पोर्टल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय और लागत को कम करता है, समग्र सरकार का दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है तथा बेहतर कनेक्टिड अवसंरचना पर फोकस करता है जिससे सुचारु सुविधा के जरिए घरेलू और निर्यात उन्मुख उद्योगों, दोनों के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी समय और लागत, दोनों में कमी आती है।

इसके अलावा, यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप), लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डूइंग बिजनेस को सरल एवं कारगर बनाने तथा लॉजिस्टिक्स में सहायता प्रदान करने वाली डिजिटल पहल है। यूलिप लॉजिस्टिक्स के लिए कागजरहित प्रकिया को सक्षम बनाता है, डाटा विश्लेषण के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप डाटा सोर्स का मानकीकरण और एकीकरण होता है। लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (एलडीबी) एक अन्य प्रौद्योगिकी संचालित पहल है जो भारत के 100 प्रतिशत कंटेनराइज्ड एग्जिम कार्गो का पता लगाने के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन), आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और बिग डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती है। इन पहलों ने दक्षता में वृद्धि की है तथा लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने में मदद की है।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंक में सुधार हुआ है जो 139 देशों में से वर्ष 2014 में 54वें स्थान से वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है।

*****